किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संविधान में 73वें तथा 74वें संशोधन के अनुसरण में, बेहतर सामुदायिक भागीदारी के लिए शिक्षा में एक विकेन्द्रीकृत ग्राम संरचना की स्थापना के लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त अनुदान दिए गए हैं उनकी सूची मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

Private investment in agriculture

1337. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the private as well as public investment in Agriculture since 1980-81;

(b) details of steps taken by Government to increase private investment in agriculture; and

(c) how far these measures have been successful till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) A statement containing details of Gross Capital Formation (Investment) in Agriculutre since 1980-81 with public and private sector break-up is enclosed (*see* below).

(b) Government have already taken a series of measures to promote private sector investment in agriculture like increased support prices, more favourable economic environment through promotion of exports and relaxation of controls on domestic movement of foodgrains, etc. In pursuance of the Union Finance Minister's speech for 1995-96, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) is proposed to be created with NABARD with the corpus of Rs. 2000 crore. The fund is proposed to be set up to counter the inadequacy of public investment in agriculture and to provide impetus to enhance the flow of credit.

(c) Private sector investment in agriculture sector has shown continuous improvement since 1987-80. In real terms by 1993-94 private sector investment in agriculture has increased by 22.5% over the position in 1987-88.

Statement

Gross Capital Formation in Agriculture (At 1980-81 Prices)

(Rs. in Crore)

Year	Gross Capital Formation in Agriculture		
	Total	Public Sector	Private Sector
1980-81	4636	1796	2840
1981-82	4503	1781	2722
1982-83	4590	1742	2348
1983-84	4101	1711	2390
1984-85	4549	1674	2875
1985-86	4325	1520	2805
1986-87	4011	1425	2586
1987-88	4414	1458	2956
1988-89	4347	1362	2985
1989-90	4353	1156	3197
1990-91	4593	1153	3440
1991-92	4497	1001	3496
1992-93	4617	1065	3552
1993-94*	4695	1074	3621

Note: * Quick Estimates
Source: National Accounts Statistics, CSO

Working group for the estimation of foodgrains requirements in 2000 A.D.

1338. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ministry have deputed a working group to prepare the estimated foodgrains requirement in 2000 A.D.;

(b) the kilo calories calculated from foodgrains and from other food sources;

(c) the major recommendations of the working group; and

(d) the steps being taken by Government on the recommendations of the working group?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) During the triennium 1991—93 the average per capita/day availability of energy from indigenous production was 2400 kcal (average daily per caput net availability of energy) including 1624 kcal from foodgrains and 776 kcal from other foods.

(c) and (d) The main recommendations of the Working Group on Foodgrains Requirements by the year 2000 A.D. set up under the Chairmanship of Shri M.S. Dayal are as under:

(i) Our current foodgrains production exceeds the normative requirements of out population by about 10%.

(ii) Under-nutrition is a matter of inadequate access of the poor to food.

(iii) In average Indian diets, if calorie requirements are met, there is no protein inadequacy.

(iv) The normative foodgrains requirement for the year 2000 A.D. assuming a population of one billion, is assessed to be 180 million tonnes (cereals, millets and pulses).

(v) Increase in foodgrains production would require a strong market pull which can be provided by a mix of aggressive exports and public stockholding.

The recommendations have been noted in the Ministry.

गुजरात में उर्वरकों की आवश्यकता

1339. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार ने वर्तमान फसल मौसम के लिए कुल कितने उर्वरकों की मांग की है;

(ख) इस समय राज्य में किन-किन उर्वरकों की अधिक मांग है और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरकों की पूरी मांग की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गुजरात की उर्वरकों की अपेक्षित मांग को पूरा करने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के दिनांक 25.8.1992 से तथा निम्न विश्लेषण नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के दिनांक 10.6.94 से विनियंत्रण के उपरान्त यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है, और इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ (अप्रैल से सितम्बर) एवं रबी (अक्तूबर से मार्च) से पहले राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के परामर्श से किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों से सभी रासायनिक उर्वरकों की संभावित आवश्यकता संबंधी सूचना मौसम से पूर्व अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली जाती है। गुजरात में खरीफ 1995 मौसम के दौरान यूरिया की प्राक्कलित आवश्यकता तथा अन्य उर्वरकों की संभावित आवश्यकता का विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	उत्पाद	प्राक्कलित/संभावित आवश्यकता (लाख मीटरी टन)
1.	यूरिया	4.80
2.	अमोनियम सल्फेट	3.05
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	0.75
4.	डाई-अमोनियम फास्फेट	2.50
5.	सिंगल सुपर फास्फेट	1.95
6.	मिश्रण	4.60
7.	म्यूरियेट आफ पोटाश	0.34

(ग) तथा (घ) खरीफ 95 के दौरान यूरिया की 4.80 लाख मीटरी टन की आवश्यकता की तुलना में गुजरात को 30.6.95 तक 2.93 लाख मीटरी टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। विनिर्माताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात में 30.6.1995 तक 2.40 लाख मीटरी टन यूरिया की बिक्री की गई। इस प्रकार गुजरात को यूरिया की सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है।